Outlay for Agriculture in Rolling Plan

3939. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Development Council has approved the basic outlines of the First Five Year Rolling Plan; and

(b) if so, the details regarding its size and whether Agriculture has been given any special consideration so far the question of outlay is concerned?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes, Sir.

(b) The overall plan size projected for 1978-83 would be Rs. 116,240 crores. Of this the public sector outlay would be Rs. 69,380 crores representing 59 7 per cent of the total plan outlay. The agriculture and irrigation sectors will receive the highest priority accounting for Rs. 18,250 crores of the outlay Special attention will be given to small and marginal farmers and landless labourers, especially from the scheduled castes and scheduled tribes. In terms of allocation, the programmes for rural development account for 43.1 per cent of the total public sector outlay.

Commissions Appointed to Enquire into Excesses during Emergency

3940. SHRI MAHI LAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the details of various Commissions appointed by the Central Government to enquire into the excesses committed during the national emergency and the amount spent on each Commission so far; and

(b) when these Commissions are likely to submit their Reports?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) Only one Commission of Inquiry (The Shah Commission) has been appointed by the Central Government to enquire into excesses committed during the Emergency. This Commission was appointed on 28-5-1977. The present term of the Commission stands sanctioned upto 30-6-1978 and an expenditure of Rs. 25,58,600/- has been incurred on the Commission upto 31-1-1978.

(b) The Commission has submitted its first interim report on the 13th March, 1978.

Manufacture of Offshore fixed Drilling-cum-Platforms

3941. DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state the progress so far made in the project for the manufacture of offshore fixed drilling-cum-platforms etc.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (PROF. SHER SINGH): The Oil and Natural Gas Commission have so far placed an order for manufacture of three offshore platforms on Mazagon Dock Ltd., Bombay. Work has commenced for fabricating these platforms in January 1978. Simultaneously, work is progressing satisfactorily for the creation of facilities for manufacture of larger number and wider range of such platforms.

आकाशवाणी में प्रशासनिक नियुक्तियों के बारे में नीति

3943. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन में प्रशासनिक नियुक्तियों व पदोन्नतियों के बारे में सरकार की नीति और प्रक्रिया क्या है ;

(ख) क्या विभिन्न भारतीय भाषाओं के मूर्धन्य साहित्यकार 'प्रोड्यूसर' या

प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव नियुक्त किए जाते है ; और

(ग) महानिदेशक, केन्द्र निदेशक आदि जैसे उच्च पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा के कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए है और उनमे से कितने व्यक्ति साहित्यकार भी थे या है और कितने साहित्यकार या कलाकार बाहर से नियुक्त किए गए है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण अडवाणी) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सम्बद्ध कार्यालय है । इन कार्यालयो मे सिविल पदो पर प्रशासनिक नियुक्तियो और पदोन्नतियों के सम्बन्ध मे नीति और प्रक्रिया वही है जो भारत सरकार के विभिन्न विभागो मे है ।

(ख) प्राड्यूसर और प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव दोनो लगभग एक से कार्य करते है और वे कार्यक्रमो की योजना बनाने और उनको तैयार करने के लिए उत्तरदायी है । इन संवर्गों मे भर्ती निर्धारित भर्ती नियमो के अनुसार की जाती है । विभिन्न भारतीय भाषाओ के प्रख्यात साहित्यकारो को प्राड्यूसर या प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवो के रूप मे नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि वे निर्धारित अर्हताए पूरी करते हों और उनका चयन भर्ती नियमों की शर्तों के अनुसार हो ।

(ग) पिछले पाच वर्षों के दौरान, आकाशवाणी और दूरदर्शन मे महानिदेशक, उप महानिदेशक और निदेशक के पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा से चार व्यक्ति और भारतीय पुलिस सेवा से दो व्यक्ति लिए गए थे । इन व्यक्तियो को इस बिना पर नियुक्त नहीं किया गया था कि वे साहित्यकार थे । पिछले पाचवर्षों के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन मे इन प्रशासनिक पदों पर बाहर से किसी साहित्यकार या कलाकार को नियुक्त नहीं किया गया ।

बिहार के पूर्वी भागों में उद्योगों की स्थापना

3944. **श्री राम सेवक हजारी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों मे उद्योगो की स्थापना को प्राथमिकता देने की नई सरकार की नीति है ;

(ख) क्या बिहार राज्य के समस्तीपुर तथा दरभगा जिले के पूर्वी भाग में उद्योग स्थापित करने की कोई योजना है ;

(ग) क्या उक्त जिले के पूर्वी भागों में उद्योग स्थापित करने से प्रस्तावित सकरी-हसनपुर रेल लाइन को यातायात मिलेगा ; और

(घ) यदि हा, तो क्या सरकार का विचार शीघ्र ही ऐसी योजना तैयार करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) : (क) जी हा ।

(ख) पुराना दरभगा जिला (जो अब दरभगा समस्तीपुर और मधुबनी नामक तीन जिलो मे विभाजित है) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना की ग्रामीण उद्योग परियोजना के अन्तर्गत आता है । पुराने दरभगा जिले को बिहार राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछडे हुए जिले के रूप मे भी चुना गया है ताकि वह वित्तीय योजना और वित्तियोजन राज सहायता की केन्द्रीय योजना दोनो का पात्र बन सके । उस क्षेत्र मे गहन हथकरघा विकास हेतु एक केन्द्रीय परियोजना भी स्थित है जिसके अन्तर्गत दरभगा और मधुबनी के नए जिले आते है ।

(ग) क्षेत्र में उद्योगो की स्थापना से सकरी-हसनपुर रेलवे लाइन पर यातायात शुरू हो जाएगा ।

(घ) जिन रेलवे लाइनो पर काम चल रहा है उनमे पर्याप्त प्रगति हो जाने पर इस लाइन पर निर्माण कार्य शुरू किये जाने का प्रस्ताव है ।